



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 20 जून, 2025
ज्येष्ठ 30, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
विद्युत नियामक भवन, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ-226010

विनियमावली संख्या यू0पी0ई0आर0सी0/डी(टी)/जेडी(पारेषण)/167-013

लखनऊ, 20 जून, 2025

यू0पी0ई0आर0सी0 (राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरण)
विनियमावली, 2025

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 181, सहपठित धारा 32 एवं धारा 33 तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनायी जाती है। यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य संबंधित प्रकरण) विनियम, 2020 को निरसित करेंगे।

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रयोज्यता एवं प्रारम्भ

(a) इस विनियमावली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरण) विनियमावली, 2025 कहा जायेगा।

(b) इस विनियमावली का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(c) यह विनियमावली राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क और प्रभारों के निर्धारण हेतु लागू होगी।

(d) यह विनियमावली आयोग द्वारा अन्यथा पहले समीक्षा करने अथवा बढ़ाये जाने के सिवाय 01 अप्रैल, 2025 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी:

परंतुकि सभी उद्देश्यों के लिए किसी वित्तीय वर्ष के लिए ए आर आर, एपीआर, टू-अप के निर्धारण से सम्बन्धित मामलों एवं सम्बद्ध विषयों, उस वर्ष विशेष पर प्रयोज्य सम्बद्ध शुल्कों एवं प्रभार विनियम से अधिशासित होंगे।

2- परिभाषाएं और निर्वचन

(1) इस विनियमावली में जब तक कि संदर्भ या विषय वस्तु में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(a) "लेखा विवरण" का तात्पर्य, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्न विवरणियों से है:-

(i) समय-समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 की अनुरूपता में तैयार की गयी सम्प्रेक्षित तुलन-पत्र,

(ii) समय-समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग-2 की आकांक्षाओं के अनुपालन में सम्प्रेक्षित लाभ-हानि विवरणी,

- (iii) समय-समय पर संशोधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के नकदी प्रवाह विवरणी (आई.एन.डी. ए.एस-3) पर लेखांकन मानकों की अनुरूपता में तैयार की गई नकदी प्रवाह विवरणी।
- (iv) एस.एल.डी.सी. के वैधानिक सम्प्रेषकों की रिपोर्ट,
- (v) समय-समय पर संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कास्ट रिकार्ड्स, यदि कोई हों,
- (vi) आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशित टिप्पणियों और समर्थक विवरणियों सहित सूचना,
- (vii) वर्ष के लिए वित्तीय विवरण से अनुकूलित लेखाकार का ट्रायल बैलेंस।
- (b) “अधिनियम” का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या-36 सन् 2003) से है।
- (c) “वार्षिक भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) प्रभार (एएलसी)” का तात्पर्य भार प्रेषण केन्द्र के वार्षिक प्रभार से है जिसमें राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्ययों को किये जाने हेतु सकल राजस्व आवश्यकता (ए आर आर सम्मिलित होगी),
- (d) “सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर)” का तात्पर्य यूपीएसएलडीसी के कारोबार से है, सम्बन्धित लागत से है जो इस विनियम के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभार से वसूल किये जाने के स्वीकृति योग्य है।
- (e) “प्राधिकरण” का तात्पर्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से है।
- (f) “आधार वर्ष” से तात्पर्य नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष से है और जो इस विनियमावली, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रयोज्य है;
- (g) “क्रेता” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो दीर्घ/मध्यम तथा लघु अवधि की मुक्त उपगम के माध्यम से विद्युत क्रय करता है तथा जिसकी शिड्युलिंग, मीटरिंग और ऊर्जा लेखांकन का समन्वय राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाता है,
- (h) “पूँजीगत व्यय” अथवा “कैपेक्स” का तात्पर्य नियंत्रण अवधि में राज्य भार प्रेषण केन्द्र की परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु किये जाने वाले अथवा योजित पूँजीकृत प्रकृतियों के व्ययों, जैसा भी प्रकरण हो, से है,
- (i) “प्रभारों” का तात्पर्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आवर्ती प्रकृति के भुगतानों की मासिक वसूली से है अथवा नियमावली में निर्दिष्ट अन्य प्रभार से है,
- (j) “विधि में परिवर्तन” से तात्पर्य निम्न में से किसी घटना के घटित होने से है –
- अधिनियमन, जिससे कोई नई भारतीय विधि प्रभाव में लाई जाती या रूख्यापित होती हो; अथवा
 - किसी वर्तमान भारतीय विधि का अभिग्रहण, संशोधन, उपांतरण, निरसन या पुनराधिनियमन; अथवा
 - न्यायिक उद्घोषणा, केंद्र एवं/या राज्य सरकार का कोई आदेश; अथवा
 - किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण अथवा उपकरण द्वारा किसी भारतीय विधि की व्याख्या या अनुप्रयोग में परिवर्तन जो विधि के अंतर्गत ऐसी व्याख्या या अनुप्रयोग के लिए अंतिम प्राधिकारी हो; अथवा
 - किसी परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त कोई सहमति, समाशोधन या अनुमोदन या अनुज्ञप्ति की शर्तों या प्रसंविदा में किसी सक्षम सांविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन; अथवा
 - भारत सरकार तथा किसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अनुबंध या संधि के प्रभावी होने या उसमें परिवर्तन, जिसका इस विनियमावली के अंतर्गत विनियमित पारेषण प्रणाली पर निहितार्थ हो; अथवा
 - जब तक कि इस विनियमावली में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी कर या शुल्क का समावेशन या ऐसे कर या शुल्क में कोई परिवर्तन।
- (k) “आयोग” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) से है,
- (l) “अनुबन्धित क्षमता” का तात्पर्य दीर्घ अवधि मुक्त उपगम अथवा मध्यम अवधि मुक्त उपगम के माध्यम से स्थापित क्षमता से है;
- (m) “नियंत्रण अवधि” से तात्पर्य 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2030 तक की पांच वर्षों की अवधि से है, जब तक कि इसे आयोग द्वारा बढ़ाया न जाए;

- (n) “शुल्क” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ग्रिड से सम्बद्धता के प्रारम्भ करने, उपगमन, शिड्युलिंग तथा पंजीकरण के कारण सदस्यता तथा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदत्त सेवाओं के लिए वापस न किये जाने वाले एक मुश्त अथवा स्थायी प्राप्त भुगतान से है;
- (o) “अपरिहार्य घटना” इस विनियमावली के उद्देश्यों से कोई घटना अथवा परिस्थितियों अथवा निम्न कथित घटनाओं अथवा परिस्थितियों के मिश्रण को सम्मिलित करते हुए जो आंशिक अथवा पूर्णरूप से एसएलडीसी को परियोजनाओं के विनियोग अनुमोदन में प्रदर्शित अवधि में पूरा करने से रोकता हो तथा ऐसी, घटनायें अथवा परिस्थितियों, जो एसएलडीसी द्वारा युक्तिसंगत सावधानी अथवा विवेकपूर्ण निगमीय अभ्यास का पालन करने के पश्चात् भी उनके नियंत्रण में न हों अथवा अपरिहार्य थी:-
- (i) ईश्वरीय कृत्य को सम्मिलित करते हुए किन्तु उसी तक सीमित नहीं, तड़ित विद्युत, सूखा, अग्नि कांड तथा विस्फोट, भूचाल, ज्वालामुखीय विस्फोट, भूमि स्खलन, बाढ़, चक्रवात, बवंडर, उग्र आंधी, भौगोलिक अप्रत्याशित घटनाएं, अथवा,
 - (ii) युद्ध, आक्रमण, सैनिक विवाद अथवा विदेशी शत्रु का कृत्य, घेराव, व्यापार प्रतिबन्ध, क्रान्ति, उपद्रव, राजद्रोह, उग्रवादी अथवा सैनिक कार्यवाही सम्बन्धी कृत्य, अथवा
 - (iii) भारत में राष्ट्रव्यापी प्रभावी औद्योगिक हड़ताल तथा श्रमिक अशान्ति।
- (p) “ग्रिडकोड” का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिडकोड से है।
- (q) “दीर्घकालिक मुक्त उपगम” का तात्पर्य ‘दीर्घकालिक मुक्त उपगम’ से है जैसा कि यूपीईआरसी (मुक्त उपगम के लिए नियम एवं शर्तें) विनियमावली, 2019 तथा इसके समय-समय पर किए गए संशोधनों, परिशिष्टों आदि में परिभाषित किया गया है।
- (r) “मध्यकालिक मुक्त उपगम” का तात्पर्य ‘मध्यकालिक मुक्त उपगम’ से है जैसा कि यूपीईआरसी (मुक्त उपगम के लिए नियम एवं शर्तें) विनियमावली, 2019 तथा इसके समय-समय पर किए गए संशोधनों, परिशिष्टों आदि में परिभाषित किया गया है।
- (s) “लघुकालिक मुक्त उपगम” का तात्पर्य ‘लघुकालिक मुक्त उपगम’ से है जैसा कि यूपीईआरसी (मुक्त उपगम के लिए नियम एवं शर्तें) विनियमावली, 2019 तथा इसके समय-समय पर किए गए संशोधनों, परिशिष्टों आदि में परिभाषित किया गया है।
- (t) “यूपीएसएलडीसी” का तात्पर्य विद्युत अधिनियम के खंड 2 के उपखंड 66 में पारिभाषित राज्यभार प्रेषण केन्द्र से है जो उत्तर प्रदेश राज्य में परिचालित है,
- (u) “प्रयोगकर्ता” का तात्पर्य उत्पादन कम्पनियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारकों, अन्य दीर्घकालिक मुक्त उपगम उपभोक्ताओं/मध्यकालिक मुक्त उपगम उपभोक्ताओं तथा आंतर-राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्ति धारकों, अर्हता प्राप्त समन्वयन अभिकरणों, या किसी अन्य इकाई से है जो आंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क या सम्बद्ध सुविधाओं या उत्तर प्रदेश राज्य भार पारेषण केन्द्र की सेवाओं के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारक के वितरण प्रणाली का प्रयोग करते हैं।
- (v) “वर्ष” से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से है;
- I. “वर्तमान वर्ष” से तात्पर्य उस वर्ष से है जिसमें वार्षिक लेखा-जोखा का विवरण या प्रशुल्क निर्धारण के लिए आवेदन दिया जाता है;
 - II. “आगामी वर्ष” से तात्पर्य वर्तमान वर्ष के अगले वर्ष से है;
 - III. “पिछला वर्ष” से तात्पर्य वर्तमान वर्ष के ठीक पहले के वर्ष से है।
- (2) शब्दों और अभिव्यक्तियों जो इस विनियमावली में प्रयुक्त हुए हैं तथा पारिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में पारिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 या आयोग के अन्य किसी विनियमावली, समय-समय पर संशोधित, के अधीन उन्हें समनुदिष्ट किये गये हैं। ऐसी अभिव्यक्तियां, जो यहां प्रयुक्त हुईं और विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विद्युत अधिनियम, 2003 में पारिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन पारिभाषित हैं और राज्य में विद्युत उद्योग पर लागू होते हैं, के वही अर्थ होंगे, जो ऐसी विधि में उनको समनुदेशित किया गया है। ऐसी अभिव्यक्ति, जो इसमें प्रयुक्त हुई है, किन्तु विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या अधिनियमों या किसी सक्षम द्वारा पारित किसी विधि में पारिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो विद्युत उद्योग में उनको सामान्यतः समनुदेशित किया जाता है।
- (3) “आवेदन” या “याचिका” शब्द की समानार्थ व्याख्या की जाएगी।

- (4) इस विनियमावली की व्याख्या में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
- (a) जैसा भी हो, एकवचन या बहुवचन वाले शब्दों में क्रमशः उनके बहुवचन या एकवचन वाले शब्द भी शामिल किये जाएंगे।
 - (b) यहां विनियमावली के प्रति किये संदर्भों को, लागू विधियों के अनुसरण में आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित या उपान्तरित विनियमावली के रूप में माना जाएगा।
 - (c) शीर्षकों को सुविधा के लिए डाला गया है और इन्हें इस विनियमावली के निर्वचन के प्रयोजनार्थ संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।
 - (d) विधानों, विनियमावली या दिशानिर्देशों के प्रति संदर्भों/निर्देशों को यथास्थिति, ऐसे विधानों, विनियमावली या दिशा निर्देशों को समेकित, संशोधित या प्रतिस्थापित करने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए माना जाएगा।
 - (e) इस विनियमावली के अंग्रेजी तथा हिन्दी पाठ के निर्वचन में किसी विवाद की दशा में अंग्रेजी पाठ प्रवृत्त होगा।

अध्याय-1

प्रशुल्क याचिका तथा प्रशुल्क निर्धारण की प्रक्रिया

3. सामान्य सिद्धांत

(1) उत्तर प्रदेश भार पारेषण केन्द्र, प्रत्येक वर्ष, विगत वर्ष के एआरआर के टू-अप, वर्तमान वर्ष के एपीआर तथा आगामी वर्ष के एआरआर/प्रशुल्क की याचिका, सर्वथा सम्पूर्ण, इन विनियमों में निर्दिष्ट स्वरूप तथा रीति में, संगत प्रारूपों के साथ, विस्तृत अभिगणनाओं द्वारा समर्थित, प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक दायर करेगा:

परंतुकि पिछले नियंत्रण अवधि के यूपीएसएलडीसी के एआरआर का टू-अप यूपीएसएलडीसी ऐसे स्वरूप तथा रीति में दायर करेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार पारेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरण) विनियमावली, 2020 में विनिर्दिष्ट है।

(2) यूपीएसएलडीसी, आयोग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर, निदेशक मंडल के उचित प्राधिकार या इस संदर्भ में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी समिति/व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित टू-अप/एपीआर/एआरआर याचिका इलेक्ट्रॉनिक रूप में दायर करेगा:

परंतुकि याचिका में ऐसे रूप में वे सूचनाएं शामिल रहेंगी जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें लेखा विवरणी, लेखा-पुस्तकों के सार तथा विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों एवं प्रारूपों के अनुसार, दूसरे ऐसे विवरण, जैसा आयोग निर्देशित करता है, शामिल रहेंगे:

परंतुकि यह भी कि यूपीएसएलडीसी पिछले प्रशुल्क आदेश में आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों लंबित के अनुपालन की वस्तुस्थिति का एक अभिकथन भी दायर करेगा।

(3) समय-समय पर संशोधित यूपीईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2019 में प्रदत्तानुसार याचिका की हार्ड प्रति भी दायर की जाएगी, जिसके साथ समय-समय पर संशोधित यूपीईआरसी (शुल्क एवं अर्थदण्ड) विनियम, 2010 के अनुसार प्रयोज्य शुल्क भी रहेगा।

(4) याचिका के प्रवेशन के पूर्व आयोग एक तकनीकी विधिमान्यकरण करेगा। अपेक्षित कार्यवाही एवं प्रस्तुतियों के पूर्ण होने तथा आयोग को संतोषजनक प्रस्तुतियों पर, आयोग याचिका को स्वीकार करेगा और एक प्रवेशन आदेश जारी करेगा।

(5) यूपीएसएलडीसी, प्रवेशन आदेश जारी होने के तीन कार्यशील दिनों के अंदर, व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो अंग्रेजी और दो हिंदी समाचारपत्रों में, एक लोक-सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें टू-अप/एपीआर/एआरआर को रेखांकित करते हुए, प्रस्तावित प्रभार तथा आयोग द्वारा निर्देशित विषय रहेंगे, तथा हितधारकों एवं जन-सामान्य से सुझावों तथा आपत्तियों को आमंत्रित किया जाएगा:

परंतुकि यूपीएसएलडीसी, अपनी वेबसाइट पर, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, टेक्स्ट-संधाननीय प्रारूप में या डाउनलोड-योग्य स्प्रेडशीट प्रारूप में, सभी नियामक फाइलिंग्स, विस्तृत अभिगणनाएं, विवरणों एवं अभिलेखों के साथ, आयोग के समक्ष दायर याचिका भी प्रदान करेगा:

परंतुकि यह भी कि इस विनियम के पहले उपबंध में उल्लिखित सूचना हेतु वेब लिंक याचिकाकर्ता की वेबसाइट पर आसानी से सुलभ, डाउनलोड हेतु संग्रहीत तथा प्रमुख रूप से प्रदर्शित होना चाहिए:

परंतु यह भी कि यूपीएसएलडीसी, अपने वेबसाइट और समाचारपत्रों के माध्यम से, अपने हित धारकों को ऐसी याचिका दायर होने की सूचना, लोक-मंत्रणा की अवधि, जन-सुनवाई की तिथि, आदि का उपयुक्त नोटिस देगा:

परंतु और भी कि आयोग याचिकाकर्ता को किसी गोपनीय समझी गई सूचना, विवरण या आलेख देने से छूट दे सकता है।

परंतु और भी कि यदि टू-अप याचिका समय सीमा के भीतर दायर नहीं होती, तो टू-अप वर्ष के अंतराल के लिए विलंब अवधि के लिए किसी प्राप्त अंतर की लागत वहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि आधिक्य की स्थिति में, उसकी वसूली वहन लागत के साथ होगी।

(6) आयोग, प्रवेशन के एक सौ बीस दिनों के भीतर, हितधारकों एवं जन-सामान्य के सुझावों तथा आपत्तियों पर विचार करके तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार:

- आदेश में निर्दिष्ट ऐसे संशोधनों या शर्तों के साथ याचिका को स्वीकार करते हुए टू-अप/एपीआर/एआरआर तथा प्रस्तावित शुल्क का आदेश जारी करेगा; या
- लिखित में कारण दर्शाते हुए, याचिकाकर्ता को सुनवाई के एक उचित अवसर के साथ, याचिका को अस्वीकृत कर देगा, यदि याचिका अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों या विधि के किन्हीं अन्य के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(7) याचिकाकर्ता आयोग द्वारा स्वीकृत शुल्क आयोग की स्वीकृति के तीन दिनों के भीतर, अपने व्यापार-क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो अंग्रेजी और दो हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा, तथा स्वीकृत शुल्क अंग्रेजी और हिंदी में अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

(8) इस प्रकार से प्रकाशित शुल्क आदेश में निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होंगे और जब तक वे संशोधित या पुनरीक्षित नहीं होते, उसमें निर्दिष्ट अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

(9) प्रस्तावित किये जाने वाले वार्षिक एलडीसी शुल्क यूपीएसएलडीसी द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित व्यय के अनुरूप और आयोग द्वारा स्वीकृत होंगे। आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक एलडीसी शुल्क (एएलसी) की वसूली मासिक आधार पर होगी। वार्षिक शुल्क में निम्नलिखित अवयव होंगे:

- परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- मूल्यवृद्धि;
- ऋण पर ब्याज;
- कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
- लाभांश;
- लाभांश पर कर;
- आयोग द्वारा स्वीकृत कोई अन्य व्यय;

ऋणात्मक

- मुक्त उपगम शुल्कों से आय;
- गैर-प्रशुल्क आय।

(10) इन विनियमों के अंतर्गत नियंत्रण अवधि में दायर की जाने वाली याचिका में निम्नलिखित होंगे:

तालिका 1: नियंत्रण अवधि में दायर की जाने वाली याचिका के विवरण

दाखिल करने की तिथि	टू-अप	ए0पी0आर0	ए0आर0आर0 / टैरिफ
30.11.2024	वित्तीय वर्ष 2023-24*	वित्तीय वर्ष 2024-25*	वित्तीय वर्ष 2025-26**
30.11.2025	वित्तीय वर्ष 2024-25***	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27
30.11.2026	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28
30.11.2027	वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29
30.11.2028	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29	वित्तीय वर्ष 2029-30

* यूपीईआरसी (राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरण) विनियमावली, 2020 के अनुसार याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं।

* *आयोग के आदेशानुसार याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के एआरआर निर्धारण के लिए, इस विनियमावली के अनुसार, और भी प्रविष्टियां मांगी जाएंगी।

* * *दायर करने का कार्य यूपीईआरसी(राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क एवं प्रभार तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरण) विनियमावली, 2020 के अनुसार होगा; तथापि, इस विनियमावली के अनुसार, याचिकाओं को संबद्ध वर्ष के 30 नवंबर तक दायर करना होगा।

- (11) नियंत्रण अवधि में दायर की जाने वाली याचिका में, यूपीएसएलडीसी, आयोग के, समय-समय पर संकलित/संशोधित, दिशानिर्देशों एवं प्रारूपों के अनुसार उपरोक्त डाटा प्रस्तुत करेगा।
- (12) यूपीएसएलडीसी द्वारा, यदि कोई जुर्माना या दंड राशि अदा की गई हो, तो उसे ए.आर.आर. (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

4-वार्षिक पूंजी निवेश योजना

- (1) यूपीएसएलडीसी को आयोग के विचारार्थ और विवेकपूर्ण परीक्षण हेतु आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले सभी पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना अपनी एआरआर याचिका में प्रस्तुत करनी होगी।
- (2) इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए, पूंजीगत व्यय परियोजना से तात्पर्य किसी स्थायी सुविधा के अधिग्रहण, निर्माण या सुधार के लिए किए जाने वाले किसी भी गैर-आवर्ती पूंजीगत व्यय कार्यक्रम से होगा।
- (3) पूंजी निवेश योजना न्यूनतम लागत योजना होनी चाहिए और इसके साथ प्रस्तावित निवेश की आवश्यकता, विचार किए गए विकल्प, लागत/लाभ विश्लेषण तथा यूपीएसएलडीसी शुल्क एवं दरों पर प्रभाव डालने वाले अन्य पहलुओं के समर्थन हेतु आवश्यक सूचनाएँ, विवरण एवं दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
- (4) पूंजी निवेश योजना में परियोजनाओं की वित्तपोषण योजना एवं भौतिक लक्ष्य शामिल होने चाहिए। समान या संबंधित प्रकृति के पूंजी निवेश कार्यों को मिलाकर एक परियोजना के रूप में माना जाना चाहिए।
- (5) सभी ऐसी पूंजीगत व्यय परियोजनाएँ जिनका मूल्य ₹1 करोड़ से अधिक हो (या आयोग द्वारा आदेश के माध्यम से या अन्यथा निर्धारित कोई वैकल्पिक सीमा), जिन्हें एआरआर याचिका में पूंजी निवेश योजना के समय सम्मिलित नहीं किया जा सका, परन्तु जिन्हें किसी आपात स्थिति के समाधान हेतु या राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल रूप से करना आवश्यक हो-ऐसी परियोजनाएँ यूपीएसएलडीसी द्वारा की जा सकती हैं। परन्तु, ऐसी परियोजनाओं के लिए, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर आयोग से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा:

परन्तुक कि, यदि उपरोक्त सीमा से अधिक पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं के लिए अनुमोदन नहीं लिया गया, तो आयोग उस वर्ष के लिए ऐसे व्यय का अधिकतम 25 प्रतिशत तक अस्वीकृत कर सकता है।

- (6) टू-अप के दौरान, अनुमोदित और पूर्ण लागत के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए, तथा महत्वपूर्ण भिन्नताओं विशेष रूप से अधिक लागत वाले मामलों में उपयुक्त औचित्य के आधार पर, पूरी पूंजीगत व्यय राशि को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

5-पूँजी लागत

- (1) परिसंपत्तियों की लागत का निर्धारण उस पूंजीगत व्यय के आधार पर किया जाएगा, जो परिसंपत्ति को वाणिज्यिक उपयोग में लाए जाने की तिथि तक वास्तव में व्यय किया गया हो, बशर्ते कि आयोग द्वारा उसका विवेकपूर्ण परीक्षण किया गया हो। वर्तमान में विद्यमान परिसंपत्तियों के मामले में, संबंधित वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियों को शुल्क निर्धारण के लिए स्वीकार किया जाएगा।
- (2) शुल्क निर्धारण के लिए ऋण-इक्विटी अनुपात 70:30 माना जाएगा। यदि प्रयुक्त इक्विटी 30 प्रतिशत से अधिक है, तो शुल्क निर्धारण हेतु इक्विटी की राशि को अधिकतम 30 प्रतिशत तक ही सीमित किया जाएगा तथा शेष राशि को मानक ऋण के रूप में माना जाएगा। वहीं, यदि वास्तविक रूप से प्रयुक्त इक्विटी 30 प्रतिशत से कम है, तो उस स्थिति में शुल्क निर्धारण के लिए वास्तविक ऋण एवं इक्विटी पर विचार किया जाएगा:

परन्तु कि—

- वार्षिक टू-अप के समय, यूपीएसएलडीसी को आंतरिक संसाधनों से की गई धनराशि की पूर्ति के समर्थन में उपयोग किए गए धन के संबंध में बोर्ड का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा;
- विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी को प्रत्येक निवेश की तिथि पर भारतीय रुपये में अभिव्यक्त किया जाएगा;
- परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त कोई भी पूंजीगत अनुदान या सब्सिडी को ऋण-इक्विटी अनुपात के निर्धारण हेतु पूंजी संरचना का भाग नहीं माना जाएगा;
- विनियमन 5(2) के अनुसार निर्धारित ऋण एवं इक्विटी की राशि का उपयोग, ऋण पर ब्याज तथा इक्विटी पर प्रतिफल की गणना हेतु किया जाएगा।

6-परिचालन एवं अनुरक्षण लागत

- यूपीएसएलडीसी के मानक परिचालन एवं अनुरक्षण लागत (ओएंडएम) की गणना तीन अवयवों, यथा (i) कर्मचारी व्यय; (ii) मरम्मत एवं अनुरक्षण (आरएंडएम) व्यय; और (iii) इन विनियमों में यथा प्रदत्त प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय। इन तीन अवयवों का योग समेकित ओएंडएम व्यय होगा, जो मानक-निर्धारण के लिए प्रयुक्त होगा:

परन्तु कि टू-अप के समय, अवयव-वार ओएंडएम व्ययों पर विचार किए बिना, समेकित ओएंडएम व्यय के आधार पर, यूपीएसएलडीसी को अंकेक्षित और मानक मूल्यों में से निम्नतर की स्वीकृति दी जाएगी।

- यूपीएसएलडीसी के ओएंडएम व्यय के प्रत्येक अवयव के मानक इन विनियमों के अनुसार निर्धारित होंगे। उसके पश्चात्, निम्नलिखित सूत्र के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए समेकित मानक ओएंडएम व्यय का अगणना की जाएगी:—

$$O\&M_n = EMP_n + R\&M_n + A\&G_n$$

जहाँ

$O\&M_n$ - O&M expenses for n^{th} year

EMP_n - Employee expenses for n^{th} year

$R\&M_n$ - R&M expenses for n^{th} year

$A\&G_n$ - A&G expenses for n^{th} year

- वेतन आयोग, पेंशन योजना में परिवर्तन आदि के प्रभाव की आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के बाद, संबद्ध अवयवों के मानक व्ययों के अतिरिक्त स्वीकृति दी जाएगी। तथापि, एक-मुश्त व्यय, जैसे वेतन-पुनरीक्षण के प्रभाव के कारण ऋणशेष का भुगतान, पेंशन योजना में परिवर्तन आदि, को संबद्ध अवयव के मानक-निर्धारण में विचारित नहीं किया जाएगा।
- यदि मानकों के अधिष्ठापन के लिए डाटा उपलब्ध नहीं है तो यूपीएसएलडीसी औचित्यकरण के साथ ओएंडएम मानक प्रस्तावित करेगा। आयोग यूपीएसएलडीसी के लिए मानकों को विवेकपूर्ण जांच के बाद स्वीकृत करेगा, जो शेष नियंत्रण अवधि पर प्रयोज्य होगा।
- यूपीएसएलडीसी प्रणाली स्वचालन, नई तकनीक तथा आईटी के क्रियान्वयन आदि के लिए ओपेक्स योजनाओं का उपक्रम कर सकता है और ऐसे व्ययों की, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच एवं पूर्व अनुमति के अधीन, मानक ओएंडएम व्ययों के अतिरिक्त स्वीकृति दी जाएगी:

परन्तु कि यूपीएसएलडीसी कैपेक्स योजनाओं की तुलना में ऐसी परियोजनाओं के विस्तृत औचित्य, लागत-लाभ विश्लेषण तथा जीवन-चक्र विश्लेषण और ओएंडएम व्ययों में बचत, यदि कोई हों, प्रस्तुत करेगा।

- यूपीएसएलडीसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी, उनमें शोधपत्रों का प्रकाशन, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त करना, लोड डिस्पैच केंद्रों में नियुक्त कार्मिकों के प्रशिक्षण और अनिवार्य प्रमाणन हेतु व्यय कर सकता है, ताकि यूपीएसएलडीसी में नियुक्त कार्मिकों को समय-समय पर विद्युत मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जा सके:

परन्तु कि यूपीएसएलडीसी ऐसे व्ययों की योजना हेतु एक रोड मैप प्रस्तुत करेगा और वार्षिक याचिका में सीईए के दिशा-निर्देशों या लागू नियमों के अनुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन/नियत रिटैनेरशिप राशि का प्रस्ताव करेगा। आयोग ऐसी प्रोत्साहन राशि/नियत रिटैनेरशिप राशि को उपयुक्त समझे जाने पर टैरिफ आदेश में अनुमोदित कर सकता है:

परन्तु कि ऐसे व्यय नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष से पृथक् रूप से कर्मचारी-व्यय शीर्षक में अपास्त किये जाएंगे, और संबद्ध वित्तीय वर्ष के एआरआर में मानक व्ययों के अतिरिक्त वास्तविक आधार पर अग्रेषित किए जाएंगे।

(7) कर्मचारी लागत

- (a) कर्मचारी मानक लागत 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच (5) वर्षों के अंकक्षित लेखा के मूल्य के औसत के आधार पर आयोग के विवेकपूर्ण जांच के अधीन व्युत्पन्न किया जाएगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंकक्षित लेखा उपलब्ध नहीं है तो पिछले पांच (5) वर्षों के अंकक्षित लेखा पर विचार किया जा सकता है, और तत्पश्चात् जब वे उपलब्ध हो जाएं तो आधार-वर्ष मूल्य (वित्तीय वर्ष 24-25) का पुनर्गणन किया जाएगा।
- (b) ऐसे कर्मचारी लागत का औसत पिछले नियंत्रण अवधि के मध्य-वर्ष (01-04-2020 से 31-03-2025 तक) के लिए कर्मचारी लागत माना जाएगा और इसमें वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होगी, जिसका वृद्धि-कारक, वित्तीय वर्ष 24-25 तक के परवर्ती वर्षों के संबद्ध वर्षों का सीपीआई होगा:

परन्तु कि वेतन पुनरीक्षण पेंशन योजना में परिवर्तन आदि जैसे एक-मुश्त के खर्चों के प्रभाव को आधार कर्मचारी लागत से हटाया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात्, मानक कर्मचारी व्यय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किए जाएंगे:-

$$EMP_n - EMP_{n-1} (1 + CPI \text{ inflation})$$

जहां:

EMP_n : Employee expense for the n^{th} year

EMP_{n-1} : Employee expense for the $(n-1)^{th}$ year

एआरआर के उद्देश्य के लिए, सीपीआई मुद्रा स्फीति भारत सरकार, श्रम ब्यूरो के अनुसार औद्योगिक कर्मचारियों (अखिल भारतीय) का ठीक पहले के तीन वित्तीय-वर्षों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत होगा।

ट्रू-अप के उद्देश्य के लिए, सीपीआई मुद्रा स्फीति संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक बिंदु से बिंदु मुद्रा स्फीति होती है।

(8) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

- (a) मानक मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन, 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच (5) वित्तीय-वर्षों के अंकक्षित लेखा में मूल्यों के औसत के आधार पर व्युत्पन्न किया जाएगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंकक्षित लेखा उपलब्ध नहीं है तो पिछले पांच (5) वर्षों के अंकक्षित लेखा पर विचार किया जा सकता है, और तत्पश्चात् जब वे उपलब्ध हो जाएं तो आधार-वर्ष मूल्य (वित्तीय वर्ष 24-25) का पुनर्गणन किया जाएगा।
- (b) ऐसे मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों के औसत को पिछले नियंत्रण अवधि (01-04-2020 से 31-03-2025 तक) के मध्यबिंदु का मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय माना जाएगा और इसमें वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होगी, जिसका वृद्धि-कारक, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के परवर्ती वर्षों के संबद्ध वर्षों का डब्ल्यूपीआई होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात्, मानक मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किए जाएंगे:-

$$R\&M_n - R\&M_{n-1} (1 + WPI \text{ inflation})$$

जहां:

$R\&M_n$: Repair & Maintenance expense for the n^{th} year

$R\&M_{n-1}$: Repair & Maintenance expense for the $(n-1)^{th}$ year

एआरआर के उद्देश्य के लिए, डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार ठीक पहले के तीन वित्तीय-वर्षों का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का औसत होगा।

ट्रू-अप के उद्देश्य के लिए, डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक बिंदु से बिंदु मुद्रा स्फीति होती है।

(9) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

- (a) मानक एंड्रजि व्यय 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले पिछले पांच (5) वर्षों के अंकक्षित लेखा के मूल्य के औसत के आधार पर आयोग के विवेकपूर्ण जांच के अधीन व्युत्पन्न किया जाएगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए अंकक्षित लेखा उपलब्ध नहीं है तो पिछले नियंत्रण अवधि (01-04-2020 से 31-03-2025 तक) के पिछले पांच (5) वर्षों के अंकक्षित लेखा पर विचार किया जा सकता है, और तत्पश्चात् जब वे उपलब्ध हो जाएं तो आधार-वर्ष मूल्य (वित्तीय वर्ष 2024-25) का पुनर्गणन किया जाएगा।

- (b) ऐसे एएंडजी व्यय का औसत पिछले नियंत्रण अवधि के मध्य-वर्ष (01-04-2020 से 31-03-2025 तक) के लिए एएंडजी व्यय माना जाएगा और इसमें वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होगी, जिसका वृद्धि-कारक, वित्तीय वर्ष 24-25 तक के परवर्ती वर्षों के संबद्ध वर्षों का डब्ल्यूपीआई होगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किए जाएंगे:-

$$A\&G_n = A\&G_{n-1} (1 + WPI \text{ inflation})$$

जहां:

$A\&G_n$: A&G expense for the n^{th} year

$A\&G_{n-1}$: A&G expense for the $(n-1)^{th}$ year

एआरआर के उद्देश्य के लिए, डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार ठीक पहले के तीन वित्तीय-वर्षों का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का औसत होगा।

ट्रू-अप के उद्देश्य के लिए, डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक बिंदु से बिंदु मुद्रा स्फीति होती है।

7-मूल्यहास

- (1) यूपीएसएलडीसी को अपने संबद्ध व्यवसायों में प्रयुक्त बद्ध आस्तियों पर मूल्य-हास की अनुमति दी जाएगी जिसका संगणन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(a) बद्ध आस्तियों की स्वीकृत मूल लागत मूल्य-हास की गणना का मूल्य आधार होगा:

परंतु कि मूल्य-हास की स्वीकृति नई आस्तियों की सम्पूर्ण पूंजीभूत राशि पर, निरसित या प्रतिस्थापित या अ-पूँजीकृत आस्तियों के स्वीकृत मूल लागत से घटा कर, स्वीकृत की जाएगी।

(b) मूल्य-हास की स्वीकृति वार्षिक आधार पर ऋजु-रेखा प्रणाली के आधार पर परिशिष्ट-क में विनिर्दिष्ट दरो पर वर्तमान आस्तियों के लिए (31-03-2025 को या उसके पूर्व) तथा नियंत्रण अवधि में पूँजीकृत आस्तियों के लिए परिशिष्ट-क में विनिर्दिष्ट दरो पर अनुमत होगी:

परंतु कि यूपीएसएलडीसी यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई एक आस्ति का मूल्य-हास सत्तर प्रतिशत हो जाता है तो समाप्त होने वाले वर्ष के 31 मार्च को शेष मूल्य-हास आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर, उनके विस्तारित जीवन को सम्मिलित करके, प्रकीर्ण कर दिया जाएगा।

(c) आस्ति का निस्तारण मूल्य पूँजी लागत का 10% होगा तथा मूल्य-हास आस्ति के स्वीकृति-योग्य पूँजी लागत का अधिकतम 90% होगा:

परंतु कि स्वामित्व वाली ज़मीन को मूल्य-हास योग्य आस्ति नहीं माना जाएगा, और मूल्य-हास की गणना के समय पूँजी लागत से अपवर्जित रहेगा:

परंतु कि यह भी कि मूल्य-हास वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से प्रभार्य होगा:

परंतु कि और भी कि आईटी उपकरणों, सॉफ्टवेयर तथा भूमिगत केबल्स का नाश रक्षण मूल्य शून्य माना जाएगा और ऐसी आस्तियों का मूल्य 100% मूल्य-हास योग्य माना जाएगा।

(d) उपभोक्ता योगदान या अनुवृत्ति या अनुदान या जमा निर्माण कार्य से पोषित आस्तियों पर हास-मूल्य की अनुमति नहीं होगी।

- (2) विद्यमान आस्तियों के संदर्भ में, मूल्य-हास की गणना के उद्देश्य से, सकल बद्ध आस्तियों का प्रारंभिक मूल्य को 31 मार्च 2025 को समापन मूल्य माना जाएगा, जैसे आयोग अपने प्रशुल्क आदेश में स्वीकृत करता है।
- (3) वर्ष के किसी भाग के लिए आस्तियों के प्रक्षेपित वाणिज्यिक परिचालन के संदर्भ में, मूल्य-हास की गणना आस्तियों के प्रारंभिक मूल्य तथा समापन मूल्य के औसत के आधार पर की जाएगी:

परंतु कि ट्रू-अप के समय पूँजीकृत आस्तियों की मूल्य-हास की पुनर्गणना, याचिकाकर्ता द्वारा पूँजीकृत आस्तियों के लेखा-विवरणों एवं प्रलेखी साक्ष्यों के आधार पर होगी, जो आयोग के विवेक पूर्ण जांच के अधीन होगा।

8-दीर्घ-कालिक ऋण पर ब्याज

(1) उपयोगाधीन आस्तियों पर, इस विनियमावली में निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार प्राप्त दीर्घ-कालिक ऋण को ऋण पर ब्याज के लिए सकल मानक ऋण माना जाएगा:

परंतु कि तुलन-पत्र में आस्तियों की सेवा-निवृत्ति या प्रतिस्थापन या अ-पूँजीकरण या निरसन/समायोजन के मामले में, उपर्युक्त स्वीकृत ऋण पूँजी, प्रलेखी साक्ष्य के आधार पर, ऐसी आस्तियों के मूल लागत के अदत्त ऋण अवयव की सीमा तक घटा दिया जाएगा।

(2) 31 मार्च 2025 को अदत्त जमा-शेष मानक दीर्घकालिक ऋण को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अदत्त अधिशेष मानक दीर्घकालिक ऋण माना जाएगा।

(3) प्रत्येक वर्ष के लिए दीर्घकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान उस वर्ष के स्वीकृत मूल्य-हास के बराबर माना जाएगा।

(4) किसी अधिस्थगन अवधि का लाभ उठाने के न होते हुए भी, ऋण पुनर्भुगतान पर आस्ति के वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष से विचार किया जाएगा।

(5) आगामी वर्ष का ब्याज दर ब्याज का भारित औसत दर होगा जिसकी आगणना पिछले वर्ष के वास्तविक दीर्घकालिक ऋण निवेश सूची के आधार पर की जाएगी:

परंतु कि यदि किसी वर्ष-विशेष में कोई वास्तविक दीर्घ-कालिक ऋण नहीं है लेकिन मानक ऋण अभी भी अप्रदत्त है, तो मानक दीर्घ-कालिक ऋण पर ब्याज की स्वीकृति के उद्देश्य के लिए, ब्याज दर, 100 आधार बिंदुओं सहित, पिछले वर्ष में प्रचलित एसबीआई एम0सी0एल0आर0 (1 वर्ष) का भारित औसत होगा।

(6) टू-अप के समय ब्याज-दर, संबंधित वर्ष की वास्तविक दीर्घ-कालिक निवेश-सूची का भारित औसत ब्याज-दर माना जाएगा:

परंतु कि यदि वर्ष-विशेष के लिए कोई वास्तविक दीर्घ-कालिक ऋण नहीं है, लेकिन मानक ऋण अभी भी अदत्त है, तो मानक दीर्घ-कालिक ऋण की अनुमति के उद्देश्य के लिए ब्याज-दर 100 आधार अंकों के साथ संबंधित वर्ष में प्रवृत्त एसबीआई एम0सी0एल0आर0 (1 वर्ष) होगा।

(7) दीर्घ-कालिक ऋण पर ब्याज-दर, भारित औसत ब्याज-दर को लागू करके, वर्ष के मानक औसत दीर्घ-कालिक ऋण पर आगणित होगा:

परंतु कि टू-अप के समय संबंधित वर्ष का मानक औसत ऋण उस वर्ष के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत वास्तविक आस्ति पूँजीकरण के आधार पर माना जाएगा।

9-बैंकिंग एवं वित्त

टू-अप में, आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन, बैंकिंग तथा वित्त प्रभार वास्तविकता के आधार पर होगा:

परंतु कि एआरआर में बैंकिंग तथा वित्त प्रभार अद्यतन टू-अप-वर्ष के लिए आयोग की स्वीकृति पर अनुमत होगा।

10-कार्यशील पूँजी पर ब्याज

(1) कार्यशील पूँजी में सम्मिलित होंगे:

(a) एक महीने का परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

(b) आयोग द्वारा यथा-स्वीकृत 45 दिनों का वार्षिक एलडीसी प्रभारों के समतुल्य अपेक्षित राजस्व:

परंतु कि उपरोक्त नियत कार्यशील पूँजी का आवश्यकता में से, जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत हो, पिछले वर्ष के 31 मार्च का राजस्व अधिशेष (यदि कोई हो), घटा दिया जाएगा:

परंतु कि यह भी कि किसी वर्ष के टू-अप के लिए कार्यशील पूँजी की आवश्यकता का पुनर्गणन टू-अप में आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूँजी के अवयवों के मूल्यों के आधार पर किया जाएगा।

(2) आगामी वर्ष के लिए कार्यशील पूँजी पर ब्याज की दर साधारण ब्याज दर होगी तथा यह, जिस दिन एआरआर के निर्धारण के लिए याचिका प्रस्तुत की जाती है, एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) जमा 250 प्वाइन्ड्स के समतुल्य होगी:

परंतु कि किसी वर्ष के टू-अप के प्रयोजनार्थ कार्यशील पूँजी पर साधारण ब्याज दर स्वीकृत किया जाएगा जो संबद्ध वर्ष में प्रचलित एसबीआई एमसीएलआर (1 वर्ष) के भारित औसत जमा 250 प्वाइन्ड्स के समतुल्य होगी।

11-लाभांश

लाभांश की गणना, ईक्विटी-आधार पर, कर के पश्चात् 14.50: वार्षिक रुपयों के रूप में की जाएगी (एतत्-पश्चात् 'आधार दर' के रूप में संदर्भित) जो इस विनियमावली के खंड 5 के अनुसार निश्चित किया जाएगा:

परंतुकि कि उपभोक्ता योगदान/जमा निर्माण कार्य/पूँजीगत अनुवृत्ति/अनुदान तथा संगत मूल्य-हास पूँजी-लागत का हिस्सा नहीं होंगे।

12-लाभांश पर कर

- (1) इस विनियमावली के खंड 11 के अंतर्गत आयोग द्वारा स्वीकृत लाभांश पर कर संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रभावी कर दर के साथ सकल-अप किया जाएगा (एतत्-पश्चात् 'टी' के रूप में संदर्भित)। प्रभावी कर दर की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में होगी जो उस वित्तीय वर्ष में यूपीएसएलडीसी पर लागू संबंधित वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा जो देय अनुमानित लाभ तथा कर पर आधारित होगा जिसमें से दूसरे व्यवसाय और उस पर प्रासंगिक कर का अपवर्जन होगा:

परंतुकि कि अपने व्यवसाय से इतर किसी आय पर कर को अग्रेषित नहीं किया जाएगा और यह स्वयं यूपीएसएलडीसी द्वारा देय होगा:

परंतुकि यह भी कि यदि यूपीएसएलडीसी आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 115 जेबी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) देता है तो प्रभावी कर दर, अधिभार एवं उपकर सहित, एमएटी दर होगा:

परंतुकि और भी कि यदि यूपीएसएलडीसी धारा 115 बीए का विकल्प लेता है तो प्रभावी कर दर आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 115 बीए में विनिर्दिष्ट, अधिभार एवं उपकर सहित, कर दर होगा।

- (2) लाभांश का दर दशमलव के तीन स्थानों तक समायोजित किया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार आगणित किया जाएगा:—

कर=पूर्व लाभांश का दर=आधार दर/(1-टी)

- (3) यूपीएसएलडीसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर का टू-अप करेगा, जो वास्तविक प्रदत्त कर पर आधारित होगा, जिसमें उस पर ब्याज सहित कोई अतिरिक्त कर मांग शामिल होगा, जिसमें इस विनियमावली के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के वास्तविक सकल आय पर प्रशुल्क अवधि से संबंधित आयकर अधिकारियों से प्राप्त ब्याज सहित कोई कर प्रतिदाय यथाविधि समायोजित होगा। इसके अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञापिधारक द्वारा देय कर की गणना के समय कर राशि के न जमा करने या कम जमा करने के कारण किसी दण्ड पर विचार नहीं किया जाएगा:

परंतुकि कि यदि यूपीएसएलडीसी आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 115 जेबी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) देता है तो यूपीएसएलडीसी लाभांश के सकल-अप दर का, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, अधिभार एवं उपकर सहित, लागू एमएटी दर सहित, टू-अप करेगा:

परंतुकि कि यदि यूपीएसएलडीसी धारा 115 बीए के अंतर्गत कर देता है तो यूपीएसएलडीसी लाभांश के सकल-अपदर का, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, धारा 115 बीए में विनिर्दिष्ट अधिभार एवं उपकर सहित, टू-अप करेगा:

परंतुकि कि, टू-अप के बाद, लाभांश के सकल-अप दर की कोई कम-वसूली या अधिक-वसूली, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, की वसूली होगी या प्रतिदेय होगी।

13-गैर-प्रशुल्क आय

- (1) यूपीएसएलडीसी के शुल्क एवं प्रभारों को निर्धारित करते समय, आयोग द्वारा स्वीकृत व्यवसाय से संबंधित यूपीएसएलडीसी की गैर-प्रशुल्क आय की राशि एआरआर से घटा दी जाएगी:

परंतुकि कि यूपीएसएलडीसी आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रारूप में अपने गैर-प्रशुल्क आय के पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगा।

- (2) गैर-प्रशुल्क आय में सम्मिलित होंगे:

- (a) भूमि या भवन के किराये की आय;
- (b) कबाड़ बिक्री से आय;
- (c) निवेशों से आय;

परंतुकि कि शेयर धारक की निधियों के निवेशों से आय, यदि कोई हो, यूपीएसएलडीसी के द्वारा आयोग को प्रस्तुत अपेक्षित विस्तृत विवरण के विवेक पूर्ण जांच के अधीन, गैर-प्रशुल्क आय में शामिल नहीं होगी;

- (d) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को दिये गए अग्रिम पर ब्याज आय;

- (e) कर्मचारियों को दिये गए ऋण/अग्रिम पर ब्याज आय;
- (f) स्टाफ़ क्वार्टर्स के किराये की आय;
- (g) ठेकेदारों के किराये की आय;
- (h) ठेकेदारों तथा अन्य से किराया प्रभार की आय;
- (i) निविदा संलेखों की बिक्री से आय;
- (j) भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य;
- (k) बीमा दावों से आय;
- (l) पूर्वावधि की आय;
- (m) विविध प्राप्तियां; तथा
- (n) अन्य कोई गैर-प्रशुल्क आय।

14-यूपीएसएलडीसी को देय शुल्क एवं प्रभार

- (1) उत्पादन कम्पनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारक, आंतर-राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, राज्य की आंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयुज्य अंतर/आंतर-राज्यीय उत्पादन कम्पनियां, मुक्त उपगम उपभोक्ता उत्तर प्रदेश भार पारेषण केन्द्र को उसके द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों, जैसे समय-सारिणी बनाना, उसका पुनरीक्षण, ऊर्जा लेखा तैयार करना, बिलिंग और डाटा एकत्रीकरण, के शुल्क देगा:

परन्तु कि विद्यमान 'प्रयोक्ताओं' को, जो पहले से ही यूपीएसएलडीसी की सेवाओं, जैसे विद्युत की समय-सारिणी तथा पारेषण, ऊर्जा लेखांकन आदि का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भुगतान या पंजीकरण नहीं किया है, उन्हें एक मुश्त पंजीकरण शुल्क तथा पंजीकरण के लिए आवश्यक देने होंगे।

- (2) यूपीएसएलडीसी आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित निम्नलिखित शुल्कों की वसूली करेगा:

- (a) सभी प्रयोक्ताओं से अनावर्ती पंजीकरण या संयोजन शुल्क;
- (b) आंतर-राज्यीय अल्प-कालिक मुक्त उपगम संव्यवहारों का शुल्क;
- (c) अल्प-कालिक मुक्त उपगम आवेदन प्रसंस्करण शुल्क;

- (3) पंजीकरण शुल्क निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा:

तालिका-1: विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण शुल्क

शुल्क का प्रकार		राशि (लाख ₹0 में)
पंजीकरण शुल्क		
A	वितरण कंपनियाँ	10.00
B	आंतर-राज्यीय अनुज्ञप्ति धारक	10.00
C	उत्पादन कम्पनियों, वशवर्ती उत्पादन संयंत्र तथा भण्डारण प्रणाली के लिए	
(i)	10 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता के लिए	0.50
(ii)	10 मेगावाट से अधिक और 100 मेगावाट की स्थापित क्षमता तक के लिए	1.00
(iii)	100 मेगावाट से अधिक स्थापित क्षमता के लिए	10.00
D	अन्य सभी प्रयोक्ता, जिसमें आंतर-राज्यीय अल्प-कालिक संव्यवहार, अर्हता प्राप्त समन्वयक अभिकरण (क्यूसीए) आदि शामिल है।	0.15

परन्तु कि अल्पकालिक मुक्त उपगम का लाभ लेने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा की गई पंजीकरण शुल्क पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक वैध होगी।

प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय

(4) अल्पकालिक मुक्त उपगम प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए आवेदन शुल्क नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है।

तालिका-2: अल्पकालिक मुक्त उपगम के लाभार्थी प्रयोक्ताओं के लिए आवेदन शुल्क

शुल्क का प्रकार		राशि (₹0 में)
आवेदन शुल्क		
1	अल्पकालिक मुक्त उपगम शुल्क (आंतर-राज्यीय आवेद/अंतरराज्य के लिए संवर्तन शुल्क)	0.07 लाख
2.	अल्पकालिक मुक्त उपगम के लिए परिचालन प्रभार	
(i)	हरित ऊर्जा मुक्त उपगम अल्पकालिक प्रयोक्ताओं के लिए	₹ 4 प्रति किलोवाट प्रतिदिन, अधिकतम ₹ 1500 प्रतिदिन की सीमा के अधीन
(ii)	हरित ऊर्जा मुक्त उपगम उपभोक्ताओं से इतर	₹ 1500 प्रतिदिन

यूपीएसएलडीसी के लिए प्रत्येक लघु अवधि द्विपक्षीय लेन-देन/सामूहिक लेन-देन के लिए दिन या दिन के किसी भी भाग के लिए उपरोक्त उल्लेखित ऑपरेटिंग शुल्क आवेदक द्वारा देय होगा:

परन्तु कि द्विपक्षीय लेन-देन के शुल्क को आवेदन जमा करने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर जमा किया जा सकता है।

15-मासिक एलडीसी प्रभार

(1) मासिक एलडीसी शुल्क (MW/माह में दशमलव के दो स्थानों तक) उन उपयोगकर्ताओं से लिया जाएगा जो मध्यम/दीर्घकालिक मुक्त उपगम प्राप्त कर रहे हैं तथा जो शेड्यूलिंग कराना चाहते हैं (लघु अवधि मुक्त उपगम को छोड़कर)। यह शुल्क बिलिंग माह के अंतिम दिन पर उनकी कुल स्वीकृत क्षमताओं के अनुपात में लिया जाएगा।

मासिक एलडीसी शुल्क निम्नलिखित सूत्र के आधार पर गणना की जाएगी।

$$AFC(u)_{(t)} = \{AFC_{(t)} \div (X_{(t)})\} / 12$$

जहाँ,

$AFC(u)(t)$ = UPSLDC Charges for the Monthly period (t);

$AFC(t)$ = Total UPSLDC Charges for the yearly period (t);

$X(t)$ = Contracted Capacity of Users who are availing

Medium/Long Term Open Access.

अध्याय-2

बिलिंग और भुगतान

16-बिलिंग और भुगतान

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच केंद्र द्वारा वार्षिक एलडीसी शुल्क (जो इन विनियमों के खण्ड 15 में प्रदत्त हैं) के आधार पर बिल मासिक रूप से तैयार किया जाएगा, जिसे अगले माह की सातवीं तिथि तक प्रस्तुत किया जाएगा। बिल की राशि बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 07 दिनों के भीतर अदा की जानी होगी।
- (2) यदि यूपीएसएलडीसी द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने के 07 दिनों के भीतर एलडीसी शुल्क का भुगतान साख-पत्र, एनईएफटी/आरटीजीएस या किसी अन्य विधि से किया जाता है, तो कर, उपकर, शुल्क आदि को छोड़कर बिल की राशि पर 01 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- (3) यदि इन विनियमों के अंतर्गत देय एलडीसी शुल्क से संबंधित किसी भी बिल का भुगतान उपयोगकर्ता द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 दिन की अवधि से अधिक विलंबित होता है, तो यूपीएसएलडीसी द्वारा प्रति माह 1.25 प्रतिशत या प्रति दिन 0.04 प्रतिशत (जो भी लागू हो) की दर से विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

अध्याय-3

विविध

17-आयोग की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति

- (1) इन विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की आयोग की अंतर्निहित शक्ति को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाला माना जाए।
- (2) इन विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया अपनाने से रोकता हो जो इन विनियमों के किसी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग किसी विषय या विषयों की श्रेणी की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना न्यायसंगत या उपयुक्त समझे।
- (3) इन विनियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पष्ट रूप से या निहित रूप में, जो आयोग को ऐसे किसी विषय से निपटने या ऐसी कोई शक्ति प्रयोग करने से रोकता हो, जिसके लिए अधिनियम के अंतर्गत कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, और आयोग ऐसे विषयों से उस प्रकार निपट सकता है जिसे वह न्यायोचित और उपयुक्त माने।

18-कठिनाइयों के अपनयन की शक्ति

यदि इस विनियमावली के किसी प्रावधान के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से, ऐसे निर्देश दे सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से विसंगत न हों, जो कठिनाइयों के अपनयन के लिए आवश्यक या उचित हों।

19-संशोधन की शक्ति

आयोग, किसी भी समय, इस विनियमावली के किसी प्रावधान में योग, रूपांतरण, परिवर्तन, उपांतरण या संशोधन कर सकता है।

20-शिथिलीकरण की शक्ति

आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसके कारणों को लेखबद्ध करना होगा और आवश्यक पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, अपने विवेक से या किसी हितधारक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलता प्रदान कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा,
सुमीत कुमार अग्रवाल,
सचिव

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

अनुलग्नक ए-31-03-2025 से पहले पूंजीकृत वर्तमान परिसंपत्तियों हेतु मूल्य ह्रास अनुसूची

परिसंपत्तियों का वर्णन		मूल्य ह्रास दर
ए	पूर्ण स्वामित्व के तहत स्वामित्व वाली भूमि	0.00
बी	पट्टे के तहत भूमि	
(क)	भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)	निर्माण स्थान की सफाई के लिए	3.34%
सी	नई खरीदी गई संपत्तियाँ:	
(क)	स्थायी किस्म के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
	(i) कार्यालय और शोरूम	3.34%
	(ii) लकड़ी की संरचना जैसे अस्थायी निर्माण	100%
	(iii) कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	3.34%
	(iv) अन्य	3.34%
(ख)	ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (कियोस्क) सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थायी उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)	
	(i) ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) जिनकी रेटिंग 100 किलोवोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक है	5.28%
	(ii) अन्य	5.28%
(ग)	केबल संयोजन सहित स्विच गियर	5.28%
(घ)	तड़ित विद्युत अवरोधक	
	(i) स्टेशन प्रकार	5.28%
	(ii) पोल प्रकार	5.28%
	(iii) सिंक्रोनस कंडेंसर	5.28%
(ङ)	बैटरी	9.00%
	(i) ज्वाइंट बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	5.28%
	(ii) केबल डक्ट सिस्टम	5.28%
(च)	सपोर्ट सहित ओवर हेड लाइनें:	
	(i) 66 वाट से अधिक सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें	5.28%
	(ii) 13.2 किलोवोल्ट से अधिक लेकिन 66 किलोवोल्ट से अधिक नहीं सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित स्टील सपोर्ट पर लाइनें	5.28%
	(iii) स्टील या प्रबलित कंक्रीट सपोर्ट पर लाइनें	5.28%
	(iv) उपचारित लकड़ी के सहारे लाइनें	5.28%

परिसंपत्तियों का वर्णन			मूल्य ह्रास दर
(छ)		मीटर	9.00%
(ज)		स्वचालित वाहन	9.00%
(प)		एयर कंडीशनिंग संयंत्र:	
	(i)	अचल	5.28%
	(ii)	चल	9.00%
(झ)		फर्नीचर और फिटिंग्स	
	(i)	कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग्स	6.33%
	(ii)	कार्यालय उपकरण	6.33%
	(iii)	आंतरिक वायरिंग जिसमें फिटिंग और उपकरण शामिल हैं	6.33%
	(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग	5.28%
(ञ)		किराए पर दिए गए उपकरण	
	(i)	मोर्टर्स से इतर	9.00%
	(ii)	मोर्टर्स	6.33%
(ट)		सॉफ्टवेयर सहित आईटी उपकरण	15.00%
(ठ)		कोई अन्य संपत्ति जो ऊपर उल्लेखित नहीं है	5.28%

टिप्पणी: परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन उपर्युक्त तालिका में दी गई मूल्य ह्रास दर के आधार पर तय किया जाएगा।

अनुलग्नक बी-31-03-2025 के बाद पूंजीकृत वर्तमान परिसंपत्तियों हेतु मूल्य ह्रास अनुसूची

परिसंपत्तियों का वर्णन			मूल्य ह्रास दर
ए		पूर्ण स्वामित्व के तहत स्वामित्व वाली भूमि	0.00
बी		पट्टे के तहत भूमि	
(क)		भूमि में निवेश के लिए	3.34%
(ख)		निर्माण स्थान की सफाई के लिए	3.34%
सी		नई खरीदी गई संपत्तियाँ:	
(क)		स्थायी किस्म के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य	
	(i)	कार्यालय और शोरूम	3.34%
	(ii)	लकड़ी की संरचना जैसे अस्थायी निर्माण	100%
	(iii)	कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	3.34%
	(iv)	अन्य	3.34%
(ख)		ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (कियोस्क) सब स्टेशन उपकरण और अन्य स्थायी उपकरण (प्लांट फाउंडेशन सहित)	
	(i)	ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) जिनकी रेटिंग 100 किलो वोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक है	4.22%
	(ii)	अन्य	4.22%
(ग)		केबल संयोजन सहित स्विचगियर	4.22%

परिसंपत्तियों का वर्णन			मूल्य ह्रास दर
(घ)		तड़ित विद्युत अवरोधक	
	(i)	स्टेशन प्रकार	4.22%
	(ii)	पोल प्रकार	4.22%
	(iii)	सिंक्रोनस कंडेंसर	4.22%
(ङ)		बैटरी	9.00%
	(i)	ज्वाइंट बॉक्स और डिस्कनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	4.22%
	(ii)	केबल डक्ट सिस्टम	4.22%
(च)		सपोर्ट सहित ओवर हेड लाइनें:	
	(i)	66 किलोवाट से अधिक सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें	4.22%
	(ii)	13.2 किलोवोल्ट से अधिक लेकिन 66 किलोवोल्ट से अधिक नहीं सांकेतिक वोल्टेज पर संचालित स्टील सपोर्ट पर लाइनें	4.22%
	(iii)	स्टील या प्रबलित कंक्रीट सपोर्ट पर लाइनें	4.22%
	(iv)	उपचारित लकड़ी के सहारे लाइनें	4.22%
(छ)		मीटर	9.00%
(ज)		स्वचालित वाहन	9.00%
(प)		एयर कंडीशनिंग संयंत्र:	
	(i)	अचल	4.22%
	(ii)	चल	9.00%
(झ)		फर्नीचर और फिटिंग्स	
	(i)	कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग्स	6.33%
	(ii)	कार्यालय उपकरणे	6.33%
	(iii)	आंतरिक वायरिंग जिसमें फिटिंग और उपकरण शामिल हैं	6.33%
	(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग	4.22%
(ञ)		किराए पर दिए गए उपकरण	
	(i)	मोर्टर्स से इतर	9.00%
	(ii)	मोर्टर्स	6.33%
(ट)		संचार उपकरण	
	(i)	रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली	15.00%
	(ii)	टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	15.00%
	(iii)	फाइबर ऑप्टिक/ओपीजीडब्ल्यू	6.33%
(ठ)		सॉफ्टवेयर सहित आईटी उपकरण	15.00%
(ड)		कोई अन्य संपत्ति जो ऊपर उल्लेखित नहीं है	4.22%

टिप्पणी: परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन उपर्युक्त तालिका में दी गई मूल्य ह्रास दर के आधार पर तय किया जाएगा।

Regulation no. UPERC/D(T)/JD(Transmission)/167-013

Dated Lucknow, June 20, 2025

**UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FEES & CHARGES OF STATE LOAD DESPATCH CENTRE AND OTHER RELATED
MATTERS) REGULATION, 2025**

IN exercise of powers conferred under Section 181 *read* with Section 32, Section 33 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations. These Regulations shall supersede the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees & Charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2020.

1. Short Title, Extent, Applicability and Commencement

- (a) These Regulations shall be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees & Charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2025.
- (b) These Regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.
- (c) These Regulations shall be applicable for determination of fees and charges to be collected by Uttar Pradesh State Load Despatch Centre from its Users.
- (d) These Regulations shall come into force from April 01, 2025, and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period of five years:

Provided that for all purposes, the issues relating to the determination of ARR, APR, True-Up and related matters for a particular financial year shall be governed by the respective Fees & charges Regulations applicable for that specific year.

2. Definitions and Interpretation

(1) In these Regulations unless the context or subject-matter otherwise requires:-

(a) “**Accounting Statement**” means for each financial year the following statements, namely:

- (i) Audited Balance sheet, prepared in accordance with the form contained in Part I of Schedule 3 to the Companies Act 2013, as amended from time to time;
- (ii) Audited Profit and loss accounts, complying with the requirements contained in Part II of Schedule 3 to the Companies Act 2013, as amended from time to time;
- (iii) Audited Cash flow statement, prepared in accordance with the Accounting Standard on cash flow Statement (IND AS-3) of the Institute of Chartered Accountants of India, as amended from time to time;
- (iv) Report of statutory auditors of UPSLDC;
- (v) Cost records if any, prescribed by the Central Government under Section 148 of the Companies Act 2013, as amended from time to time;
- (vi) Together with notes thereto, and such other supporting statements and information as the Commission may direct from time to time;
- (vii) Trial Balance for the year matching the accounts with Financial Statements.

(b) “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;

(c) “**Annual Load Despatch Centre Charges (ALC)**” means the charges as determined by the Commission from time to time and levied by Uttar Pradesh State Load despatch Centre for recovery of its Aggregate Revenue Requirement (ARR) as approved by the Commission in accordance with these Regulations;

(d) **“Aggregate Revenue Requirement” or “ARR”** means the costs pertaining to UPSLDC business which are permitted to be recovered from the fees and charges determined by the Commission, in accordance with these Regulations;

(e) **“Authority”** means Central Electricity Authority;

(f) **“Base Year”** means the financial year immediately preceding first year of the Control Period of these Regulations *i.e* FY2024-25;

(g) **“Buyer”** means a person buying power through Long/Medium/Short-Term Open Access and whose scheduling, metering and energy accounting is coordinated by Uttar Pradesh State Load Despatch Centre;

(h) **“Capital Expenditure” or “Capex”** means the expenditure of capital nature incurred or planned to be incurred for creation of assets of Uttar Pradesh State Load Despatch Centre;

(i) **“Charges”** means recurring payments on monthly basis or otherwise to be collected by Uttar Pradesh State Load Despatch Centre as specified in the Regulations;

(j) **“Change in law”** means occurrence of any of the following events:-

(i) enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law or;

(ii) adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law; or

(iii) judicial pronouncements, Orders of Central Government and / or State Government; or

(iv) change in interpretation or application of any Indian law by a competent Court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality which is the final authority under law for such interpretation or application; or

(v) change in condition or covenant by any competent statutory authority in relation to any consent or clearances or approval or License available or obtained for the project; or

(vi) coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement / or treaty between the Government of India and any other Sovereign Government having implication for UPSLDC regulated under these Regulations;

(vii) Any change in taxes or duties, or introduction of any taxes or duties levied by the Central or any State Government, unless specified otherwise in this Regulation.

(k) **“Commission”** means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC);

(l) **“Contracted Capacity”** means the capacity arranged through Long term Open Access or Medium term Open Access;

(m) **“Control Period”** means the period comprising of five financial years from April 1, 2025 to March 31, 2030, unless extended by the Commission;

(n) **“Fees”** means the non-refundable one-time or fixed payments collected by Uttar Pradesh State Load Despatch Centre for the services rendered for commencement of grid access, scheduling and on account of registration, membership or any other purpose as specified by the Commission from time to time;

(o) **“Force Majeure”** for the purpose of these Regulations means the event or circumstance or combination of events or circumstances including but not limited to those stated below that wholly or partly prevents or unavoidably delays UPSLDC from completing the project within the time specified in the Capital Investment Approval/contract agreement, and only if such events or circumstances are not within the control of UPSLDC and could not have been avoided, had UPSLDC taken reasonable care or complied with prudent utility practices,-

(i) Act of God including but not limited to lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises; or

(ii) Any Act of war, invasion, armed conflict or Act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action; or

(iii) Industry wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India.

-
- (p) **“Grid Code”** means U.P. Electricity Grid Code as amended from time to time;
- (q) **“Long-term Open Access”** means ‘Long-term Open Access’ as defined in UPERC (Terms and conditions for Open Access) Regulation, 2019 and its subsequent amendments & addendums *etc.*;
- (r) **“Medium-term Open Access”** means ‘Medium-term Open Access’ as defined in UPERC (Terms and conditions for Open Access) Regulation, 2019 and its subsequent amendments & addendums *etc.*;
- (s) **“Short-term Open Access”** means ‘Short-term Open Access’ as defined in UPERC (Terms and conditions for Open Access) Regulation, 2019 and its subsequent amendments & addendums *etc.*;
- (t) **“UPSLDC”** means the State Load Despatch Centre as defined in sub-section (66) of section (2) of Electricity Act, which is operating in the State of Uttar Pradesh;
- (u) **“User”** means the Generating Companies, Distribution Licensees, other Long term Open Access Customers/ Medium term Open Access Customers and Intra-State transmission licensees, Qualified Coordinating Agency (QCA), or any other such entity which uses the Intra-State transmission network or the associated facilities or distribution system of Distribution Licensee through services of Uttar Pradesh State Load Despatch Centre;
- (v) **“Year”** means the financial year ending on 31st March,—
- (i) **“Current Year”** means the year in which the statement of annual accounts or application for determination of Tariff is filed;
 - (ii) **“Ensuing Year”** means the year next following the current year;
 - (iii) **“Previous Year”** means the year immediately preceding the current year.

(2) The words and expressions used in these Regulations and not defined herein, but defined in the Act or any other Regulation of the Commission, shall bear the same meaning as in the Electricity Act, 2003 or any other Regulations of the Commission, as amended from time to time. Expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Electricity Act, 2003 or in any of the Commission’s Regulations but defined under any law passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law. Expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act or any law passed by a competent legislature shall have the meaning as is generally assigned in the electricity industry.

- (3) The words “Application” or “Petition” shall be used interchangeably.
- (4) In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:
- (a) words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;
 - (b) references herein to the “Regulations” shall be construed as a reference to these Regulations as amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;
 - (c) the headings are inserted for convenience and may not be taken into account for the purpose of interpretation of these Regulations;
 - (d) references to the Statutes, Regulations or Guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or Guidelines, as the case may be;
 - (e) in case of dispute in interpretation between English and Hindi version of these Regulations, the English version shall prevail.

CHAPTER- 1

TARIFF PETITION AND PROCEDURE FOR DETERMINATION OF TARIFF**3. General Principles**

(1) Uttar Pradesh State Load Despatch Centre shall file an Annual Petition complete in all respect every year during control period for True-up of ARR for previous year, APR of current year and ARR / Tariff of ensuing year in such form and in such manner as specified in these Regulations along with relevant formats, duly supported with detailed computations, by 30th November of each year:

Provided that True-up of ARR of UPSLDC for those years falling under past control period shall be filed by UPSLDC in such form and in such manner as specified in Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Fees & Charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2020.

(2) UPSLDC shall file the True-Up/ APR/ ARR Petition, electronically on e-filing portal of the Commission, after due authorization by the Board of Directors or by any Committee/person authorised by the Board in this regard, digitally signed by the authorized representative:

Provided that the Petition shall include information in such form as may be stipulated by the Commission, together with the Accounting Statements, extracts of books of account and such other details, as per the Guidelines and Formats prescribed or directions given by the Commission:

Provided further that UPSLDC shall also submit a statement on the status of compliance to the directives issued by the Commission in the previous Tariff Orders which are pending for compliance.

(3) Hard copies of the Petition shall also be filed as provided for in the UPERC (Conduct of Business) Regulation, 2019 as amended from time to time, accompanied with applicable fees as per the UPERC (Fee and Fines) Regulation, 2010 as amended from time to time.

(4) The Commission shall conduct a Technical Validation before admission of the Petition. On completion of the required proceedings and submissions made to the satisfaction of the Commission, the Commission will admit the Petition and shall issue an Admittance Order.

(5) UPSLDC shall within three working days of issue of the Admittance Order, publish a Public Notice in at least two English and two Hindi daily newspapers having wide circulation, outlining the True-Up/APR/ARR, proposed charges and such other matters as may be directed by the Commission, and inviting suggestions and objections from the stakeholders and public at large:

Provided that UPSLDC shall also provide on its website the Petition filed before the Commission along with all regulatory filings, detailed computations, particulars and documents, in text-searchable format or in downloadable spreadsheet format in the manner stipulated by the Commission:

Provided also that web link to the information mentioned in the first proviso to this Regulation should be easily accessible, archived for downloading and to be prominently displayed on the Petitioner's website:

Provided also that UPSLDC shall intimate its stakeholders about filing of such Petition, period of public consultation, date of Public Hearing *etc.* through appropriate notice on its website and newspapers:

Provided further that the Petitioner may be exempted by the Commission from providing any such information, particulars or documents considered confidential in nature:

Provided further that if the True-Up Petition is not submitted within timelines, no carrying cost for the period of delay shall be allowed for the gap arrived for the true-up year. However, in case of surplus, the same shall be recovered with carrying cost.

(6) The Commission shall, within one hundred and twenty days from admittance, after considering all suggestions and objections received from the stakeholders and public at large and in accordance with the provisions contained in these Regulations:

(a) Issue an Order for True-Up/ APR/ ARR & proposed charges accepting the Petition with such modifications or such conditions as may be specified in that Order; or

(b) Reject the Petition for reasons to be recorded in writing if such Petition is not in accordance with the provisions of the Act and the Rules and Regulations made there under or any other provisions of law, after giving the Petitioner a reasonable opportunity of being heard.

(7) The Petitioner shall publish the Charges approved by the Commission within three working

days after approval by the Commission in at least two English and two Hindi daily news papers having wide circulation in its business area and shall upload the approved Charges on its internet website in English and Hindi.

(8) The charges, so published, shall be in force from the date stipulated in the Order and shall, unless amended or revised, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.

(9) The annual LDC charges shall correspond to the expenditure proposed to be incurred by UPSLDC and as approved by the Commission. The annual LDC charges (ALC) as approved by the Commission shall be recovered on monthly basis. The annual charges shall consist of the following components, namely:-

- (a) Operation & Maintenance Expenses;
- (b) Depreciation;
- (c) Interest on Loan;
- (d) Interest on Working Capital;
- (e) Return on Equity;
- (f) Tax on Return on Equity;
- (g) Any other expenses approved by the Commission;

Minus;

- (h) Income from Open Access charges;
- (i) Non-Tariff Income.

(10) The Petitions to be filed in the Control Period under these Regulations will comprise of the following:-

Filing date	True- Up	APR	ARR / Tariff
30.11.2024	FY 2023-24*	FY2024-25*	FY 2025-26**
30.11.2025	FY 2024-25***	FY 2025-26	FY 2026-27
30.11.2026	FY 2025-26	FY 2026-27	FY 2027-28
30.11.2027	FY 2026-27	FY 2027-28	FY 2028-29
30.11.2028	FY 2027-28	FY 2028-29	FY 2029-30

**The Petitions have already been filed as per UPERC (Fees & Charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulation, 2020.*

***As per the directions of the Commission, the Petitions have already been filed. Further submissions will be sought as per these Regulations for determination of ARR for FY 2025-26.*

****The filings shall be as per UPERC (Fees & Charges of State Load Despatch Centre and other related matters) Regulation, 2020, however, filings have to be made on 30th November of the respective year as per these Regulations.*

(11) UPSLDC shall submit the data regarding the above as per Guidelines and Formats prescribed and added / amended from time to time by the Commission in its Petition to be filed during the Control Period.

(12) Fine or Penalties paid, if any, by UPSLDC shall not be allowed as part of ARR.

4. Annual Capital Investment Plan

(1) For the purpose of these Regulations, a capital expenditure project shall mean any non-recurring capital expenditure programme for the acquisition, construction or improvement of a permanent facility.

(2) UPSLDC shall submit a detailed Capital Investment Plan for all capital expenditure project(s) that it plans to undertake during the ensuing year in its ARR Petition for consideration and prudence check of the Commission.

(3) The capital investment plan shall be a least cost plan for undertaking investment and shall be accompanied by such information, particular and documents as may be required for substantiating the need for the proposed investments, alternatives considered, cost/benefit analysis and other aspects that may have a bearing on UPSLDC Fees & Charges.

(4) The Capital Investment Plan shall include financing plan and physical targets of the Project(s) to be undertaken by UPSLDC and Capital Investment works of similar or related nature should be clubbed and considered as a project.

(5) All capital expenditure projects exceeding the value of ₹ One Crore or any alternate threshold stipulated by the Commission, through an Order or otherwise, which could not be included in the Capital Investment Plan at the time of submission of ARR Petition but are required to be undertaken immediately to cater to an emergency or to implement a State Government or Central Government funded scheme, may be undertaken by UPSLDC. However, approval of the Commission for such projects undertaken in each quarter should be sought within one month of the closure of that quarter.

Provided that in case approval is not taken for the capital expenditure for projects exceeding the above thresholds, the Commission may disallow up to 25% of such capital expenditure for that year.

(6) During the True-Up, the final approval to the entire capital expenditure shall be granted considering the variation between approved and completed cost with justification for significant variations, particularly on the higher side.

5. Capital Cost

(1) Cost of assets shall be determined based on capital expenditure actually incurred as on the date of putting the asset in commercial use subject to prudence check by the Commission. In case of existing assets, net fixed assets as per audited annual accounts as on April 1st of the corresponding financial year shall be taken for the purpose of determination of charges.

(2) The debt-equity ratio shall be 70:30 for determination of charges. Where equity employed is more than 30%, the amount of equity for determination of charges shall be limited to 30% and the balance shall be considered as the normative loan. In case where actual equity employed is less than 30%, the actual debt and equity shall be considered for determination of charges.

Provided that,—

(a) UPSLDC, at the time of annual True-Up, shall submit the resolution of the board regarding infusion of fund from internal resources in support of the utilization made to meet the capital expenditure;

(b) The equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment;

(c) Any capital subsidy or grant obtained for the execution of the project shall not be considered a part of capital structure for the purpose of debt-equity ratio;

(d) The debt and equity amount arrived at in accordance with Regulation 5(2) shall be used for calculating interest on loan and return on equity.

6. Operation and Maintenance Expenses

(1) The normative Operation and Maintenance (O&M) expenses for UPSLDC shall be computed for three components *i.e* (i) Employee Expenses, (ii) Repair and Maintenance (R&M) Expenses, and (iii) Administrative and General Expenses as provided in these regulations. The sum of these three components shall be the consolidated O&M expenses, which shall be considered for benchmarking:

Provided that at the time of True-Up, UPSLDC shall be allowed lower of audited or normative value based on the consolidated Operation & Maintenance Expenses irrespective of component wise O&M expenses.

(2) The Norms for each component of O&M Expenses shall be determined as per these Regulations. Thereafter consolidated normative O&M Expenses for each year of the Control Period shall be computed based on the formula shown below:—

$$\mathbf{O\&M_n = EMP_n + R\&M_n + A\&G_n}$$

Where:

O&M_n - O&M expenses for nth year

EMP_n - Employee expenses for nth year

R&M_n - R&M expenses for nth year

A&G_n - A&G expenses for nth year

(3) The impact of Pay Revision, change in Pension Scheme *etc.*, shall be allowed by the Commission over and above normative expenses of the respective component after prudence check. However, one-time expenses such as payment of arrears due to impact of pay revision, change in pension scheme *etc.*, shall not be considered for determination of norm of the respective component.

(4) In case data required for establishing the norms is not available, UPSLDC shall propose O&M norms with justification. The Commission shall approve the norms for UPSLDC after prudence check, which shall be applicable for the remaining Control Period.

(5) UPSLDC may undertake Opex schemes for system automation, new technology and IT implementation, *etc.*, and such expenses may be allowed over and above normative O&M Expenses, subject to prior approval and prudence check by the Commission:

Provided that UPSLDC shall submit detailed justification, cost benefit analysis, and life-cycle cost analysis of such schemes as against Capex schemes and savings in O&M Expenses, if any.

(6) UPSLDC may undertake expenses towards participation in national and international conferences, publication of papers therein, facilitating higher education, availing institutional membership with national bodies and international bodies, training and mandatory certification of personnel posted in the load dispatch centres, to ensure that personnel deployed in UPSLDC are trained as per the MoP/CEA guidelines issued from time to time:

Provided that UPSLDC may submit the roadmap for planning of such expenses and shall propose incentives/ fixed retainer-ship amount for employees acquiring the certificate in accordance with CEA guidelines or as per applicable rules in the Annual Petition. The Commission may allow such incentives/ fixed retainer-ship amount in the tariff Order as it considers deemed fit:

Provided further that these expenses shall be booked separately under Employee expenses from the first year of the Control Period and shall be passed through on actual basis in ARR of respective financial year over and above the normative expenses.

7. Employee Cost

(a) The normative Employee Cost shall be derived on the basis of the average of the values in the Audited Accounts for the last five (5) financial years ending March 31, 2025 subject to prudence check by the Commission. However, if Audited Accounts are not available for FY 2024-25, Audited Accounts available for the last five (5) years will be considered and subsequently when the same becomes available the base year value (*i.e.* FY 2024-25) will be recomputed.

(b) The average of such Employee Cost shall be considered as Employee Cost for the middle year of the previous Control Period (01.04.2020 to 31.03.2025) and shall be escalated year on year with the escalation factor considering CPI of respective years, for subsequent years up to FY 2024-25:

Provided that impact of one time expenses such as arrears due to impact of pay revision, change in pension scheme, *etc.* shall be removed from the base Employee Cost.

After arriving at the figure of FY 2024-25, the normative employee expenses shall be computed as per formula below:-

$$\mathbf{EMP_n = EMP_{n-1} \times (1 + \text{CPI inflation})}$$

Where:

EMP_n: Employee expense for the nth year

EMP_{n-1}: Employee expense for the (n-1)th year;

For the purpose of ARR, CPI inflation is the average of Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers (All India) as per Labour Bureau, Government of India for the immediately preceding three financial years.

For the purpose of True-Up, CPI inflation is the actual point to point inflation for the concerned financial year.

(8) Repairs and Maintenance Expense

(a) The normative Repair and Maintenance expenses shall be derived on the basis of the average of the values in the Audited Accounts for the last five (5) financial years ending March 31, 2025 subject to prudence check by the Commission. However, if Audited Accounts are not available for FY 2024-25, Audited Accounts available for the last five (5) years will be considered and subsequently when the same becomes available the base year value (*i.e.* FY 2024-25) will be recomputed.

(b) The average of such Repair and Maintenance expenses shall be considered as Repair and Maintenance expenses for the middle year of the previous Control Period (01.04.2020 to 31.03.2025) and shall be escalated year on year with the escalation factor considering WPI of respective years, for subsequent years up to FY 2024-25:

After arriving at the figure of FY 2024-25, the normative R&M expenses shall be computed as per formula below:-

$$R\&M_n = R\&M_{n-1} (1 + \text{WPI inflation})$$

Where:

$R\&M_n$: Repairs & Maintenance expense for n^{th} year;

$R\&M_{n-1}$: Repairs & Maintenance expense for the $(n-1)^{\text{th}}$ year;

For the purpose of ARR, WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three financial years as per the Office of Economic Advisor of Government of India:

For the purpose of True-Up, WPI inflation is the actual point to point inflation for the concerned financial year.

(9) Administrative and General Expenses

(a) The normative A&G Expenses shall be derived on the basis of the average of the values in the Audited Accounts for the last five (5) financial years ending March 31, 2025 subject to prudence check by the Commission. However, if Audited Accounts are not available for FY 2024-25, Audited Accounts available for the last five (5) financial years of previous Control Period (01.04.2020 to 31.03.2025) will be considered and subsequently when the same becomes available the base year value (*i.e.* FY 2024-25) will be recomputed.

(b) The average of such A&G Expenses shall be considered as A&G Expenses for the middle year of the previous Control Period (01.04.2020 to 31.03.2025) and shall be escalated year on year with the escalation factor considering WPI of respective years, for subsequent years up to FY 2024-25.

After arriving at the figure of FY 2024-25, the normative A&G expenses shall be computed as per formula below:

$$A\&G_n = A\&G_{n-1} (1 + \text{WPI inflation})$$

Where:

$A\&G_n$: A&G expense for the n^{th} year;

$A\&G_{n-1}$: A&G expense for the $(n-1)^{\text{th}}$ year;

For the purpose of ARR, WPI inflation is the average of Wholesale Price Index (WPI) for immediately preceding three financial years as per the Office of Economic Advisor of Government of India:

For the purpose of True-Up, WPI inflation is the actual point to point inflation for the concerned financial year.

(7) Depreciation

(1) UPSLDC shall be permitted to recover Depreciation on the value of fixed assets used in their respective businesses, computed in the following manner:

(a) The approved original cost of the fixed assets shall be the base value for the calculation of Depreciation:

Provided that the Depreciation shall be allowed on the entire capitalised amount of new assets after reducing the approved original cost of the retired or replaced or de-capitalised assets.

(b) Depreciation shall be allowed annually based on the Straight- Line Method at the rates stipulated in Annexure-A for existing assets (capitalised on or before 31.03.2025) and at the rates stipulated in Annexure-B for assets capitalised during this Control Period:

Provided that UPSLDC shall ensure that once individual asset is depreciated to the extent of seventy percent, the remaining depreciable value as on 31st March of the year closing shall be spread over the balance Useful Life of the assets including the Extended Life, as per submission of UPSLDC and approval by the Commission.

(c) The salvage value of the asset shall be considered at 10% of the allowable capital cost and Depreciation shall be allowed up to a maximum of 90% of the allowable capital cost of the asset:

Provided that land owned shall not be treated as a Depreciable asset and shall be excluded from the capital cost while computing Depreciation:

Provided further that Depreciation shall be chargeable from the first year of commercial operation:

Provided that the salvage value of the IT equipment, software and underground cable shall be considered as nil and value of such assets shall be considered 100% depreciable.

(d) Depreciation shall not be allowed on assets funded by Consumer Contributions or Subsidies/ Grants/ Deposit works.

(2) In case of existing assets, for the purpose of computation of depreciation, the opening value of GFA shall be taken as the closing value as on March 31, 2025 as approved by the Commission in its Tariff Order.

(3) In case of projected commercial operation of the assets for part of the year, depreciation shall be computed based on the average of opening and closing value of assets:

Provided that the depreciation shall be re-computed for assets capitalised at the time of Truing-Up, based on Accounting Statements and documentary evidence of assets capitalised by the Petitioner, subject to prudence check of the Commission.

(8) Interest on Long- Term Loan

(1) The long- term loans arrived at in the manner indicated in these Regulations on the assets put to use shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan:

Provided that in case of retirement or replacement or de-capitalisation or deletion/adjustment of the assets in the balance sheet, the loan capital approved as mentioned above shall be reduced to the extent of outstanding loan component of the original cost of such assets based on documentary evidence.

(2) The closing normative long- term loan outstanding as on March 31, 2025 shall be taken as the opening normative long term loan outstanding for the financial year 2025-26.

(3) The repayment of long-term loans for each year shall be deemed to be equal to the Depreciation allowed for that year.

(4) Notwithstanding any moratorium period availed, the repayment of loan shall be considered from the first year of commercial operation of the asset.

(5) The rate of interest for ensuing year shall be the weighted average rate of interest computed on the basis of the actual long-term loan portfolio of previous year:

Provided that if there is no actual long- term loan for a particular year but the normative loan is still outstanding, then the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative long- term loan shall be the weighted average of SBI MCLR (1 year) prevailing during the previous year plus 100 basis points.

(6) At the time of Truing-Up, the weighted average rate of interest of the actual long- term loan portfolio during the concerned year shall be considered as the rate of interest:

Provided that if there is no actual long-term loan for a particular year but the normative loan is still outstanding, then the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative long-term loan shall be the weighted average of SBI MCLR (1 year) prevailing during the concerned year plus 100 basis points.

(7) The interest on long-term loan shall be calculated on the Normative Average long-term loan of the year by applying the Weighted average rate of interest:

Provided that at the time of Truing-Up, the normative average loan of the concerned year shall be considered on the basis of the actual asset capitalisation approved by the Commission for the year.

(9) Banking and Finance Charges

The Banking & Finance charges shall be allowed as per actuals in Truing-Up, subject to prudence check by the Commission:

Provided that the Banking and Finance charges shall be allowed in ARR as per the approval given by the Commission for the latest True-Up year.

(10) Interest on Working Capital

(1) The working capital shall cover:

(a) Operation and maintenance expenses for one month;

(b) Receivables equivalent to 45 days of annual LDC charges as approved by the Commission:

Provided that the working capital requirement determined above shall be reduced by the amount of revenue surplus (if any) as of 31st March of the previous year as approved by the Commission:

Provided further that for the purpose of Truing- Up for any year, the working capital requirement shall be re-computed on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the Truing- Up.

(2) Rate of interest on working capital for ensuing year shall be simple interest and shall be equal to the SBI MCLR (1-year) as on date on which Petition for determination of ARR is filed plus 200 basis points:

Provided that for the purpose of Truing- Up for any year, simple interest on working capital shall be allowed at a rate equal to the weighted average SBI MCLR (1-year) prevailing during the concerned year plus 200 basis points.

(11) Return on Equity

Return on equity shall be computed in ₹ terms on equity base at the rate of 12.50% post-tax per annum (hereinafter referred to as 'Base Rate') for UPSLDC as determined in accordance with clause 5 of this Regulation:

Provided that assets funded by Consumer Contribution, Capital Subsidies / Grants and corresponding Depreciation shall not form part of the Capital Cost.

(12) Tax on Return on Equity

(1) The rate of return on equity as allowed by the Commission under clause 11 of these Regulations shall be grossed up with the effective tax rate (hereinafter referred to as 't') of the respective financial year. The effective tax rate shall be calculated at the beginning of every financial year based on the estimated profit and tax to be paid estimated in line with the provisions of the relevant Finance Act applicable for that financial year to UPSLDC by excluding the income of other business and the corresponding tax thereon:

Provided that tax on any income other than that through its Business shall not be pass through and it shall be payable by UPSLDC itself:

Provided that in case UPSLDC is paying Minimum Alternate Tax (MAT) under Section 115JB of the Income Tax Act, 1961, the effective tax rate shall be the MAT rate, including surcharge and cess:

Provided further that in case UPSLDC has opted for Section 115BAA, the effective tax rate shall be the tax rate including surcharge and cess as specified under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961.

(2) The rate of return on equity shall be rounded off to three decimal places and shall be computed as per the formula given below.

Rate of pre-tax return on equity = Base rate / (1-t)

(3) UPSLDC shall true up the effective tax rate for every financial year based on the actual tax paid together with any additional tax demand, including interest thereon, duly adjusted for any refund of tax including interest received from the income tax authorities pertaining to the Tariff period covered under these Regulations on actual gross income of any financial year. Further, any penalty arising on account of delay in deposit or short deposit of tax amount shall not be considered, while computing the actual tax paid by UPSLDC:

Provided that in case UPSLDC is paying Minimum Alternate Tax (MAT) under Section 115JB, UPSLDC shall true up the grossed up rate of return on equity at the end of every financial year with the applicable MAT rate including surcharge and cess:

Provided further that in case UPSLDC is paying tax under Section 115BAA, UPSLDC shall true up the grossed up rate of return on equity at the end of every financial year with the tax rate including surcharge and cess as specified under Section 115BAA:

Provided also that any under-recovery or over recovery of grossed up rate on return on equity after true-up, shall be recovered or refunded, on a year to year basis.

13. Non-Tariff Income

(1) The amount of Non-Tariff Income relating to UPSLDC Business as approved by the Commission shall be deducted from the ARR in determining the Fees and Charges of UPSLDC:

Provided that UPSLDC shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission in such form as may be stipulated by the Commission.

(2) The Non-Tariff Income shall include:

- (a) Income from rent of land or buildings;
- (b) Income from sale of scrap;
- (c) Income from investments:

Provided that income arising from investment of shareholder's funds, if any shall not be included in Non-Tariff income subject to prudence check of requisite detailed information submitted by UPSLDC before the Commission.

- (d) Interest income on advances to suppliers/contractors;
- (e) Interest income on loans / advances to employees;
- (f) Income from rental from staff quarters;
- (g) Income from rental from contractors;
- (h) Income from hire charges from contractors and others;
- (i) Income from sale of tender documents;
- (j) Excess found on physical verification;
- (k) Income from Insurance Claim;
- (l) Prior Period Income;
- (m) Miscellaneous receipts; and
- (n) Any other Non-Tariff Income.

(13) Fee and Charges payable to UPSLDC

(1) The Generating companies, Distribution Licensees, Intra-State Transmission Licensees, Inter/Intra State generating companies connected with Intra-State Transmission power system of the State, Open Access Customers shall pay a fee to Uttar Pradesh State Load Despatch Centre for duties like scheduling and revision of schedules, preparation of energy account, billing and data collection, to be rendered by it:

Provided that the existing "Users" who are already availing the services of UPSLDC like Scheduling and Despatch of electricity, Energy Accounting etc. but have not paid or yet not registered, shall have to provide one time registration fee and all relevant documents required for registration.

(2) UPSLDC shall recover the following Fees as approved by the Commission from time to time:

- (a) One time Registration or Connection Fees from all users;
- (b) Scheduling/ operating charges for intra-State short-term Open Access transactions;
- (c) Short-term Open Access Application Processing Fees.

(3) The Registration fee shall be paid as shown in the table below: -

Table 1: Registration Fees for different users

Nature of Fee		Amount (₹ Lakhs)
Registration Fees		
A	Distribution Companies	10.00
B	Intra State Transmission Licensees	10.00
C	For Generating Companies, captive generating plant and Standalone Storage System	
(i)	Having installed capacity upto 10 MW	0.50
(ii)	Having installed capacity more than 10 MW and upto 100 MW	1.00
(iii)	Having installed capacity of more than 100 MW	10.00
D	All Other Users including Inter-State Short-Term transactions, Qualified Coordinating Agency (QCA) etc.	0.15

Provided that the registration fees submitted by users availing Short Term Open Access shall be valid from the date of registration till completion of one year.

Application Fee

(4) The Application Fee for the Users availing Short Term Open Access as provided in the table below:

Table 2: Application Fees applicable for Users availing Short-Term Open Access

S. No.	Nature of Fee	Amount (₹)
Application Fees		
1	Short Term Open Access Fee (Intra State Application/concurrence fee for Inter State)	0.07 Lakh
2	Operating Charges for Short-Term Open Access	
(i)	For Green Energy Open Access short Term Users	₹4/kW/day subject to ceiling of 1500/day
(ii)	Other than Green Energy Open Access Users	₹1500/day

The Operating charges as mentioned above for day or part of the day for each Short-term bilateral transaction/collective transaction for Uttar Pradesh State Load Despatch Centre shall be payable by the applicant:

Provided that the fee of bilateral transactions may be deposited within three working days of submission of the application.

(14) Monthly LDC Charges

(1) The Monthly LDC charges in MW/Month upto two decimal places to be taken from the Users who are availing Medium / Long Term Open Access and who want to get the scheduling done (except short term Open Access), in proportion to the sum of their capacities as on the last day of the billing month.

The Monthly LDC charges shall be calculated based on the following formula:

$$AFC(u)_{(t)} = \{AFC_{(t)} \div (X_{(t)})\}/12$$

Where,

AFC(u)(t) = UPSLDC Charges for the Monthly period (t);

AFC(t) = Total UPSLDC Charges for the yearly period (t);

X(t) = Contracted Capacity of Users who are availing Medium/Long Term Open Access.

CHAPTER-2

Billing and Payment**(15) Billing and Payment**

(1) Uttar Pradesh State Load Despatch Centre shall raise bill based on Annual LDC Charges as provided in clause 15 under these Regulations to be presented by seventh day of next month. Bill shall be paid within 7 days from the day of presentation of bill.

(2) For payment of bills of LDC charges through Letter of Credit or through NEFT/RTGS or otherwise, within 7 days of presentation of bills by UPSLDC, a rebate of 1% on billed amount, excluding the taxes, cess, duties, etc., shall be allowed.

(3) In case the payment of any bills for LDC charges payable under these Regulations is delayed by the user beyond a period of 30 days from the date of presentation of bills a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month or 0.04% per day, as the case may be, shall be levied by UPSLDC.

CHAPTER- 3

Miscellaneous**(16) Inherent Powers of the Commission**

(1) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice.

(2) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters, deems it just or expedient for deciding such matter or class of matters.

(3) Nothing in these Regulations shall, expressly or implied, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters in a manner, as it considers just and appropriate.

(17) Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific Order, give directions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

(18) Power to Amend

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

(19) Power to Relax

The Commission may, by general or special Order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the necessary parties, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

By the Order of the Commission,

SUMEET KUMAR AGARWAL,

Secretary,

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

Annexure -A**Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised on or before 31.03.2025**

Description of Assets		Depreciation Rate
A.	Land owned under full title	0.00--
B.	Land held under lease	
(a)	for investment in the land	3.34%
(b)	for cost of clearing the site	3.34%
C.	Assets Purchased New:	
(a)	Building & civil engineering works of permanent character	
	(i) Offices & showrooms	3.34%
	(ii) Temporary erection such as wooden structures	100%
	(iii) Roads other than kutchra roads	3.34%
	(iv) Others	3.34%
(b)	Transformers, transformer (Kiosk) sub-Station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)	
	(i) Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	5.28%
	(ii) Others	5.28%
(c)	Switchgear including cable connections	5.28%
(d)	Lightning arrestors	
	(i) Station type	5.28%
	(ii) Pole type	5.28%
	(iii) Synchronous condenser	5.28%
(e)	Batteries	9.00%
	(i) Underground Cable including joint boxes and disconnected boxes	5.28%
	(ii) Cable duct system	5.28%
(f)	Overhead lines including supports:	
	(i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kV	5.28%
	(ii) Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts	5.28%
	(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports	5.28%
	(iv) Lines on treated wood supports	5.28%
(g)	Meters	9.00%
(h)	Self propelled vehicles	9.00%
(i)	Air conditioning plants:	
	(i) Static	5.28%

Description of Assets			Depreciation Rate
	(ii)	Portable	9.00%
(J)		Furniture and Fittings	
	(i)	Office furniture and fittings	6.33%
	(ii)	Office equipment	6.33%
	(iii)	Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
	(iv)	Street light fittings	5.28%
(k)		Apparatus let on hire	
	(i)	Other than motors	9.00%
	(ii)	Motors	6.33%
(l)		I.T. equipment including software	15.00%
(m)		Any other assets not covered above	5.28%

Note: Useful life of the assets shall be derived based on the depreciation rate provided in the above table.

Annexure-B**Depreciation Schedule for Existing Assets Capitalised After 31.03.2025**

Description of Assets		Depreciation Rate
A.	Land owned under full title	0.00--
B.	Land held under lease	
(a)	for investment in the land	3.34%
(b)	for cost of clearing the site	3.34%
C.	Assets Purchased New:	
(a)	Building & civil engineering works of permanent character	
	(i) Offices & showrooms	3.34%
	(ii) Temporary erection such as wooden structures	100%
	(iii) Roads other than kutchra roads	3.34%
	(iv) Others	3.34%
(b)	Transformers, transformer (Kiosk) sub-Station equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)	
	(i) Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	4.22%
	(ii) Others	4.22%
(c)	Switchgear including cable connections	4.22%
(d)	Lightning arrestors	
	(i) Station type	4.22%
	(ii) Pole type	4.22%
	(iii) Synchronous condenser	4.22%
(e)	Batteries	9.00%
	(i) Underground Cable including joint boxes and disconnected boxes	4.22%
	(ii) Cable duct system	4.22%
(f)	Overhead lines including supports:	4.22%
	(i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kV	4.22%
	(ii) Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 13.2 kilovolts but not exceeding 66 kilovolts	4.22%
	(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports	4.22%
	(iv) Lines on treated wood supports	4.22%
(g)	Meters	9.00%
(h)	Self propelled vehicles	9.00%
(i)	Air conditioning plants:	
	(i) Static	4.22%
	(ii) Portable	9.00%
(j)	Furniture and Fittings	
	(i) Office furniture and fittings	6.33%

Description of Assets			Depreciation Rate
	(ii)	Office equipment	6.33%
	(iii)	Internal wiring including fittings and apparatus	6.33%
	(iv)	Street light fittings	4.22%
(k)		Apparatus let on hire	
	(i)	Other than motors	9.00%
	(ii)	Motors	6.33%
(l)		Communication Equipment	
	(i)	Radio and High- Frequency Carrier System	15.00%
	(ii)	Telephone lines and telephones	15.00%
	(iii)	Fibre Optic/OPGW	6.33%
(l)		I.T. equipment including software	15.00%
(m)		Any other assets not covered above	4.22%

Note: Useful life of the assets shall be derived based on the depreciation rate provided in the above table.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 75 राजपत्र-2025-(228)-588 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 9 सा० रुर्जा-2025-(229)-100+500=600 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।